राजस्व विभाग में विभिन्न प्रभागों / संगठनों के कार्य

प्रशासन प्रभाग:

राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले। विभाग और भारतीय राजस्व सेवा (समूह - क), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह - क) के सचिवालय के अधिकारीयों और कर्मचारियों के सीआर डोजियर का रखरखाव। भाषाओं के अनुवाद और राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित समन्वय कार्य और कार्य।

बिक्री कर प्रभाग :

बिक्री कर कानूनों (वैधता) अधिनियम, 1956, केंद्रीय बिक्री कर, राज्य-स्तरीय मूल्य वर्धित कर (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989 आदि का प्रशासन।

नारकोटिक्स नियंत्रण प्रभाग:

अफीम की खेती, अफीम के उत्पादन और अफीम के निर्यात और मूल्य निर्धारण के लिए लाइसेंसिंग नीति का निर्धारण। प्रबंधन समिति के कामकाज का समन्वय और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दे।

प्रबंधन समिति:

विभागीय उपक्रमों जैसे कि सरकारी अफीम और अल्कलॉइड वर्क नीमच (M.P.) और गाजीपुर जो निर्यात उद्देश्यों के लिए कच्ची अफीम के प्रक्रमण में लगे हुए हैं और अफीम से अल्कलॉइड के संग्रह के लिए भी उपयोग किया जाता हैं, जो औषधीय उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है।

समीक्षा आवेदन इकाई:

आयुक्त, सीमा शुल्क (अपील) और आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आदेशों और सीबीईसी के खिलाफ 11.10.1982 से पहले दर्ज किए गए मामलों में संशोधन के आवेदन से संबंधित कार्य।

एकीकृत वित्त इकाई:

राजस्व विभाग और सीबीडीटी और सीबीईसी के अंतर्गत क्षेत्रीय इकाइयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना। व्यय और वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित सभी कार्य करता है । राजस्व, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर विभाग से संबंधित अनुदान के लिए व्यय बजट तैयार करना .

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड :

अप्रत्यक्ष करों के करारोपण एवं उदग्रहण से संबंधित सभी मामले।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड:

अप्रत्यक्ष करों के करारोपण एवं उदग्रहण से संबंधित सभी मामले।

सक्षम प्राधिकारी कक्ष :

तस्करी और विदेशी विनिमय मैनिपुलेटर्स (संपत्ति का त्याग) अधिनियम, 1976 का प्रशासन और ज़ब्त संपत्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित मुद्दे।

सक्षम प्राधिकरण:

तस्करी और विदेशी विनिमय मैनिपुलेटर्स (संपत्ति का त्याग) अधिनियम, 1976 और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कार्य।

ज़ब्त संपत्ति के लिए अपीलीय प्राधिकरण :

सफेम (एफओपी) अधिनियम, 1976 और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय V ए के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित संपत्तियों को जब्त करने के आदेशों के खिलाफ व्यक्तियों द्वारा दायर की गई अपील का अधिनिर्णयन।

सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण :

कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्तों (अपील) के आदेशों के खिलाफ सुनवाई।

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के प्रचार के लिए राष्ट्रीय समिति:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एसी के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश करना।

अग्रिम नियमों के लिए प्राधिकरण :

लेन-देन के संबंध में गैर-निवासियों द्वारा दायर एक आवेदन में निर्दिष्ट कानून या तथ्य के सवाल पर अग्रिम फैसले देना, जो आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है।

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग :

सीमा शुल्क अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निर्धारितियों द्वारा दायर किये गए आवेदनों का निपटान।

निपटान आयोग (आईटी / डब्ल्यूटी) :

आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम, 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दायर किये गए आवेदनों का निपटान।

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:

आर्थिक गतिविधियों की जांच और आर्थिक कानूनों को लागू करने से संबंधित विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुफिया जानकारी जुटाने की गतिविधियों का समन्वय और मजबूती, खोजी प्रयास और प्रवर्तन कार्रवाई।

प्रवर्तन निदेशालय:

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए जिम्मेदार। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत नज़रबंदी में लेने के मामलों की सिफारिश करना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत , प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यतः जांच और अधिनिर्णयन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है।

वित्त आसूचना इकाई:

धन शोधन और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के संग्रह और साझाकरण को समन्वित और मजबूत करना।